

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
30.07.2014 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2906

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

2906. श्री चिन्तामन नावाशा वांगा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारत और अमरीका के बीच परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात, देश में परमाणु ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;
- (ख) क्या भारत और अमरीका के बीच परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात, देश में कोई अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है;
- (ग) यदि हाँ, तो विभिन्न परमाणु संयंत्रों में कितने मेगावाट वर्धित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है; और
- (घ) वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत का किन-किन देशों के साथ समझौता हुआ है और भविष्य में किन-किन देशों के साथ ऐसा समझौता होने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क), (ख) तथा (ग) जी, हाँ। वर्तमान में, 4680 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत हैं, 1840 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर आयातित ईंधन को उपयोग में ला रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहकार करार के सम्पन्न होने से पहले, केवल 320 मेगावाट क्षमता के रिएक्टरों (तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2) में आयातित ईंधन के उपयोग में लाया जाता था। वर्ष 2008 में अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की वजह से, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन वाले अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के लिए ईंधन का आयात करना संभव हो पाया है। आयातित ईंधन की उपलब्धता की वजह से ईंधन का मांग-आपूर्ति के बीच का अंतर भी कम हो गया है, जिसकी वजह से, तीन नए रिएक्टरों नामतः राजस्थान में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 5 तथा 6 (2x220 मेगावाट) और कर्नाटक में कैगा-4 (220 मेगावाट)का वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरु करना संभव हो पाया है, जिसके परिणामस्वरूप देश में नाभिकीय विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। अतः, अंतर्राष्ट्रीय सहकार के परिणामस्वरूप, 1520 मेगावाट तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो पाई है।
- (घ) वर्तमान में, भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जिन देशों के साथ करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, रूस, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिणी कोरिया, कजाखिस्तान तथा चेक गणराज्य। आस्ट्रेलिया, जापान तथा श्रीलंका के साथ बातचीत जारी है।
